Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

द्वितीय सप्रु हाउस व्याख्यान

द्वारा

एडमिरल (सेवानिवृत्त) अरूण प्रकाश

पूर्व नौसेना अध्यक्ष

विषय

"21वीं सदी में चीन की समुद्री चुनौती"

स्थान
सप्रु हाउस, नई दिल्ली
30 अक्तूबर, 2012

सभापति महोदय,अतिविशिष्ट अतिथिगण, मित्रों, देवियों एवं सज्जनों

मैं भारत के विदेश नीति विशेषज्ञों , रणनीतिकारोंव प्रसिद्ध शिक्षाविदों तथा नेपाल के मित्रों और शुभेक्षुओं के इस महान समूह को संबोधित करने के इस अवसर को पाकर सत्कृत और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर इस महान कार्यक्रम के आयोजन तथा नेपाल-भारत संबंधों के कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (आईसीडब्लूए) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

आपको यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि दो पड़ोसी मित्र देशों -नेपाल और भारत के बीच के संबंधों की स्थिति चिर काल से ही बहुत ही उत्कृष्ट , निकटता वाला, सौहार्द्रपूर्ण एवं बहु आयामी रही है। हमारा संबंध इतिहास , सांस्कृतिक लोकाचारों, परंपराओं और रिवाजों से पोषित रहा है जिसकी प्रकृति अद्वितीय है और ऐसा संबंध विश्व में शायद हीं किन्हीं देशों के बीच हो। उसी प्रकार लोगों के बीच का संबंध सदियों से विकसित हुआ है जिसमें आर्थिक प्रगति , समृद्धि और शांति के लिए साझा आकांक्षाएं हैं। साथ ही , मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमारे द्विपक्षीय सहयोग को अर्थपूर्ण तरीके से मजबूत करने की और क्षमताएं हैं। मैं पाता हूं कि हमारे सम्मुख विशाल अवसर हैं। हमें अपने दोनों देशों के बीच प्राचीन सौहार्द्रपूर्ण संबंधों का निर्माण करना चाहिए तथा आर्थिक व वाणिज्यिक सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों के बीच वास्तविक संबंध को मजबूत करना चाहिए। परस्पर लाभ के लिए इन क्षमताओं की व्यवहारिक अनुभूति ही अगले दशक में भारत-नेपाल संबंध का हमारा विजन है। मुझे आपके साथ इस विजन पर अपने विचार को साझा करने में बड़ी खुशी है। मैं आज की परस्पर बातचीत के लिए ऐसे महत्वपूर्ण विषय को चुनने के लिए आईसीडब्लूए को धन्यवाद देता हूं।

भारत सदियों से महान सभ्यता का एक देश है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत और इसके लोगों ने ब्रिटिश औपनिवेशवाद के विरूद्ध अपने अथक संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आजादी का रास्ता दिखाया है और अन्य देशों में ऐसे संघर्ष का समर्थन किया है। महात्मा गांधी जैसे भारतीय नेताओं की अगुवाई वाले स्वतंत्रता संग्राम की रोशनी का विश्व भर में कई देशों पर गुंजायमान प्रभाव पड़ा है जो देश ब्रिटिश औपनिवेशवाद के प्रभाव में थे। यदि मैं यह कहूं कि भारत विश्व भर में आधिपत्य और अन्याय के विरूद्ध संघर्ष में कई देशों के लिए प्रेरणा रहा है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी।

चीनी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक समृद्धि में देश की धारणीय बढ़ोतरी का इस्तेमाल उसकी अपनी सैन्य शक्ति को सतत रूप से बढ़ाने और समुद्री, अंतरिक्ष व सूचना युद्धक क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाए। प्रत्येक राष्ट्र को हर वह कदम उठाने का अधिकार है जिसे वह अपने राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता है किंतु चीन की कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था , जो गोपनीयता के प्रति अभिभूत है , ने अपने विशाल सैन्य विस्तार पर कोई विचार नहीं किया है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने कुछ साल पहले शांगरी -ला संवाद में चीनी प्रतिनिधिमंडल से इस सवाल के जवाब में पारदर्शिता नहीं बरतने के बारे में सार्वभौमिक चिंताओं का हवाला दिया : *"चूंकि कोई भी देश चीन को धमकी नहीं देता है, इसलिए किसी को आश्चर्य होना चाहिए : आक्रामक प्रणालियों में निवेश क्यों बढ़ रहा है ; क्यों इन बड़े और महंगे हथियारों की खरीद जारी हैं?"* उन्हें एक वरिष्ठ पीएलए जनरल से जो प्रतिक्रिया मिली उस प्रतिक्रिया ने श्रोताओं को और भी अधिक भ्रमित कर दिया।

1962 का ज़ख्म

हममें से जो लोग 1950 के दशक में बड़े हुए उन्हें "पंचशील" और गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्मरण होगा जो अक्सर सुर्खियों और रेडियो समाचारों में आया करते थे। हमने अक्सर समाचार पत्रों और न्यूज रीलों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई की मुस्कुराहट भरी तस्वीरें देखीं ; और प्रसिद्ध नारा था: "हिंदी-चीनी भाई-भाई" जिसे भारतीय जनता ने अच्छे विश्वास के साथ उत्साह से अपनाया। 1950 में चीन ने तिब्बत के स्वतंत्र राज्य पर आक्रमण किया और इसे एक स्वायत्त गणराज्य के रूप में शामिल किया। 1951 में जब भारत ने तिब्बत पर चीनी आधिपत्य को स्वीकार किया , किंतु कुछ जानकारों ने महसूस किया कि यह एक विशाल बफर राज्य को खत्म कर देगा, और चीन हमारे उत्तरी द्वार तक आ जाएगा जिसका परिणाम घातक होगा।

1962 में चीन के हाथों भारत की अपमानजनक सैन्य हार , कई मायनों में एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई। उन लोगों के लिए तो इस हार ने उनके शालीन विचार -प्रक्रिया से राजनीतिक नेतृत्व को हिला दिया , जिसने माना था कि अहिंसा और पंचशील हमें आक्रामकता से मुक्त कर देगा। नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया : " *हम आधुनिक दुनिया में वास्तविकता से बाहर हो रहे थे और अपने स्वयं के बनी एक कृत्रिम दुनिया में रह रहे थे "।* अपनी समग्र व्यापक दृष्टि और राज्य-कौशल के लिए नेहरू को सशस्त्र बलों के लिए एक तिरस्कार हासिल हुआ , जिसे वे राज्य की नीति के एक साधन के रूप में निरर्थक मानते थे। पश्च दृष्टि में यह स्पष्ट है कि भारतीय नेतृत्व , जिसने 1949 में चीन के नए विजयी कम्युनिस्ट शासन के इरादों को भांप नहीं सका , ने कुछ व्यावहारिक सुझावों को भी नजरअंदाज कर दिया था , जिन्होंने चेतावनी देने की कोशिश की थी।

भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने तिब्बत के संबंध में पंडित नेहरू को नवंबर 1950 में एक विस्तृत पत्र लिखा था, जिसमें यह चेतावनी थी: *"चीनी सरकार ने हमें शांतिपूर्ण इरादों के बल पर बहकाने की कोशिश की है...। एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान वे हमारे देश में घुसने में कामयाब रहे। राजदूत ने तिब्बती समस्या को*

शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने की अपनी तथाकथित इच्छा में विश्वास की झूठी भावना के साथ तिब्बत पर हमले के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए किया।

जिस राजदूत का पटेल ने संदर्भ दिया वे हैं सरदार केएम पनिक्कर जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से ही पेकिंग में सेवा दी थी। यह बड़ा दिलचस्प है कि पनिक्कर ने 1945 में लिखी अपनी पुस्तक 'इंडिया एंड द इंडियन ओशन' में इसका उल्लेख किया : '*कि चीन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर नौसेना के विस्तार को शुरू करना है जो राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दोनों की प्रवृत्तियों से एकदम स्पष्ट है ..... मार्क्सवादियों ने मांग की है कि जापानी नौसेना को युद्ध के बाद उनके हवाले कर दिया जाना चाहिए।*'

हम जानते हैं कि "*किसी भी महान व्यक्ति का सम्मान उनके अपने देश में नहीं किया जाता है*", इसलिए हो सकता है कि पटेल और पनिक्कर को नजरअंदाज किया गया हो , किंतु चीन की ओर हमारी उभयवृत्तिता अब 65 वर्ष की हो गयी है।

भारत की द्वैधवृत्ति

1962 की दर्दनाक घटनाओं के बाद की आधी सदी में , भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में स्पष्टता की कमी बनी हुई है कि कैसे हमें पीआरसी के लिए नीतियां तैयार करनी चाहिए और उसके प्रति अपने रणनीतिक रुख को आकार देना चाहिए। यह अस्पष्टता चीन के अतीत के कृत्यों और बयानों साथ ही साथ हमारे स्वयं के, हाल ही के अनुभवों के आलोक में भू-राजनीतिक महत्व की व्याख्या करने में असमर्थता से उत्पन्न होती है।

पीआरसी के प्रति हमारा संकोच अज्ञात डर अर्थात् इस विशाल पड़ोसी देश के बारे में हमारी गहरी अज्ञानता के कारण है। हमने न तो देश में मैंडरिन बोलने वालों का समूह तैयार किया है और न ही चीन के इतिहास , संस्कृति, अर्थव्यवस्था, उद्योग और रणनीतिक विचारों के शोध के लिए समर्पित संगठनों को तैयार किया है। इसके परिणामस्वरूप चीनी क्षमता के बारे में हमारा आंकड़ा छिटपुट है और हम उनके वक्तव्य की बारीकियों और दीर्घकालिक इरादों के बारे में अंधेरे में तीर चलाते हैं।

विचित्र विकृतियों के साथ हम वर्षों से उस व्यापक अवसर को ठुकरा रहे हैं जो पीआरसी में हमें ताईवान आफर करता रहा है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हाल की चीनी कार्रवाई और वक्तव्यों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं में स्पष्टता और संकल्प का आभाव रहा है।

अन्य संबंधित राष्ट्रों निश्चय ही इस मामले में लापरवाह नहीं रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने न केवल वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रक्षा विभाग को अधिदेश दिया है बल्कि चीन की सैन्य शक्ति के संबंध में नियमित सूचना प्रदान करने के लिए अपनी सम्मेलन संबंधी अनुसंधान सेवा का भी भार दिया है। अमेरिका में हुए सभी

अध्ययनों में वर्तमान में मुद्दा सबसे अधिक ध्यान इस पर दिया मालूम पड़ता है जिसे शोध शब्दों में "समुद्र की ओर चीन का रूख" कहा जा सकता है; जो विशेष रूप से इसके नाटकीय नौसेना आधुनिकीकरण के संबंध में है।

चीन का समुद्री भाग की ओर मुड़ना

जहां तक भारत का संबंध है , चीनी-भारतीय रणनीतिक समीकरण में समुद्री आयाम अपेक्षाकृत एक नया कारक है। दोनों ही देशों के तीव्र आर्थिक विकास के कारण ऊर्जा और कच्चे मालों पर निर्भरता में बढ़ोतरी हुई है जिसे वे संसार भर से प्राप्त करते हैं और इनकी ढुलाई समुद्री मार्ग से की जाती है। इससे दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का ध्यान तेजी से व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए समुद्री लेने के अबाधित उपयोग पर पड़ा है। संवर्धित प्रौद्योगिकी के साथ समुद्री तल को उत्तरोत्तर ऊर्जा और खनिज संपदा के संभावित प्राचुर्य स्थल के रूप में देखा जाता है ; इस प्रकार प्रादेशिक विवाद का कारण विशेष रूप से आर्थिक जोन है।

हम भारत में चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति की घटना का विश्लेषण किए बिना स्वयं ही सामान्य रूप से "स्ट्रिंग आफ पर्ल रणनीति" जैसे सामान्य मुहावरे सहित अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा स्वीकृत रेखा को स्वीकार कर चुके हैं। जहां अमेरिकी विश्लेषक का फोकस इस चुनौती पर है कि चीन हिंद -प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, वहीं हमें अमेरिकी अतिश्योक्ति और भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा सहजता के संदर्भ में इतिहास को देखने और आने वाले वर्षों में अपने हितों के लिए चीन की समुद्री चुनौती पर यथार्थवादिता से फोकस करना है।

चूंकि विश्व के ये दो विशाल भूभाग , स्थलाकृति और सैन्य शक्तियां - भारत और चीन - अपनी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को गति देने और अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने पड़ोसियों को असहज बना रहे हैं। दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों , जो एक दूसरे के इतने निकट हैं , को एक साथ विकास करने के लिए निपुण कूटनीति से या चमत्कार या फिर दोनों तरीकों से विवाद के बिना ही कार्य करना होगा।

वास्तव में चीन की समुद्री चुनौती पर कार्य शुरू करने से पूर्व देश को अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विभिन्न पहलुओं को समझने में कुछ समय देना चाहिए जो पहलू भारत -चीन के विकास क्रम को बताने और एक -दूसरे के प्रति हमारी अवधारणा को समझने में सहायक होगा। इसलिए, थोड़ी देर तक मेरे साथ बने रहें।

भारत-चीन संबंधों का विकास क्रम

जब भारत का स्वतंत्रता के लिए अहिंसात्मक संघर्ष 1947 में समाप्त हुआ तो चीन लगभग चार दशकों के लिए खूनी संघर्ष में घिरा हुआ था जिसके दौरान यह इंपीरियल शासन व्यवस्था मुक्त हो गया था और गृह युद्ध और क्रूर जापानी कब्जे का सामना कर रहा था; और इसने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। अंत में 1949 में साम्यवादियों ने कुओमिंटांग पार्टी के राष्ट्रवादियों को हरा दिया और उन्हें ताइवान की ओर धकेल दिया। जहां भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना , वहीं विजयी साम्यवादियों ने मुख्य भूमि चीन पर कठोर सर्वसत्तात्मक व्यवस्था को थोप दिया।

पश्चिमी शक्तियों ने पीआरसी को मान्यता देने से मना कर दिया और ताइवान को संयुक्त राष्ट्र व सुरक्षा परिषद् में जगह दी गयी। इसी समय प्रधानमंत्री नेहरू ने सक्रिय रूप से इस आशा के साथ पीआरसी का पक्ष लिया कि ये दो राष्ट्र औपनिवेशवाद से संघर्ष करने के लिए एशिया का विशाल गठबंधन कर सकता है। इस प्रकार , भारत उन कुछ राष्ट्रों में से

एक था जिसने चीन का संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सदस्यता की वकालत की जो वास्तव में 1971 में हुआ।

यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि गृह युद्ध की समाप्ति के तत्काल बाद वरिष्ठ चीनी साम्यवादी नेतृत्व ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे; पहला यह कि चीन महाशक्तियों के समतुल्य परमाणु शक्ति बनेगा; और दूसरा यह कि वह एशिया के नेतृत्व के लिए किसी प्रतिस्पर्धी को बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्वासघाती चीन ने अक्तूबर , 1962 में आक्रमण किया, इसलिए यह न केवल भारत की सुरक्षा पर वास्तविक प्रहार था बल्कि सैन्य हार के अपमान से हमारी राष्ट्रीय आत्मा पर आघात पहुंचा: यह परिणाम ऐसा ही था जो चीन चाहता था।

जैसा कि हेनरी किसिंगर ने हाल ही में अपनी पुस्तक *ऑन चाइना* में कहा कि माउ से तुंग के लिए यह कोरिया में अमेरिकी अनुभव का प्रत्युत्तर था ; *"एक एजवाजयरी द्वारा चीन को कम आंकना , दोषपूर्ण गुप्त सूचना आकलन, और इस बात को समझने में गंभीर खामी कि चीन आसन्न सुरक्षा खतरों के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है।"* कूटनीतिक माध्यमों से स्वयं को आश्वस्त करते हुए कि अमेरिका अपनी हिमालयी जोखिम में हस्तक्षेप नहीं करेगा , और कि संधि साझेदार यूएसएसआर उसकी सहायता कर सकता है , माओ ने अक्तूबर, 1962 की शुरूआत में अपने सीएमसी सहयोगियों को एकत्र किया और व्यंग्यात्मक रूप से घोषणा की : *"चूंकि नेहरू अपनी बुद्धि पर चल रहा है और हमसे युद्ध पर जोर दे रहा है , हमारे लिए युद्ध नहीं करना मित्रता नहीं होगी। शिष्टाचार की मांग है कि हम प्रत्युत्तर दें।"*

पचास वर्ष बाद, हम एक पूरा चक्र घूम चुके हैं; जहां चीन बार-बार और आक्रमक तरीके से भारत के भूभाग पर अपना दावा कर रहा है और ऐसी मुद्रा बनाए हुए है जो 1962 की याद दिलाता है। यह इस पृष्ठभूमि के प्रतिकूल है कि भारतीयों को कई मुद्दों के बारे में पूर्णत: स्पष्ट रहना चाहिए जिस पर चीन-भारत संबंध उभर रहा है।

प्रथम; आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा , चाहे यह कितना भी असममित क्यों न हो , किंतु यह इस बात को अपरिहार्य बनाता है कि दोनों ही देशों को एशिया में उसी रणनीतिक क्षेत्र में होड़ करना पड़ेगा। इस प्रतिस्पर्धा को उदार चमक देने के हमारे प्रयास को चीन के अपने भूभाग संबंधी दावों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिरोधी रूख के कोलाहल पूर्ण पुनरावृत्तियों से झुठलाया जाता है।

दूसरा, जहां भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है वहीं चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। किंतु यदि हम इतने भर से संतुष्ट हो जाएं तो यह व्यापार ट्रोजन अश्व साबित हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से व्यापार ने कभी भी राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हितों अथवा युद्ध करने से नहीं रोका है।

तीसरा, चीन ने हमारे आसपास के देशों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान कर भारत को घेरने का सतर्क प्रयास किया है। इस संदर्भ में फारस की खाड़ी में अवस्थित ग्वादर और श्रीलंका के दक्षिण पूर्व मुहाने पर स्थित हम्बनटोटा हिंद महासागर के रणनीतिक पत्तन दो ऐसा पत्तन हैं जिन्हें चीन विकसित करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2012 का चीन का 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट हमारे अपने बजट से तीन गुना है , और यह अमेरिका के बाद सबसे अधिक बजट है। और यह पता चला है कि इतनी ही राशि को गुप्त रूप से रणनीतिक बलों और विशेष परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। चीन का सैन्य विस्तार और आधुनिकीकरण इस उद्देश्य की कुल जटिलता को बतलाता है, और इतनी बड़ी राशि के व्यय करने का औचित्य बतलाने अथवा अपने पड़ोसी देशों को आश्वस्त करने के लिए अपनी ओर से उसने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।

और अंत में, इस तरीके का कोई पूर्वोद्धारण नहीं है जिस तरीके से चीन हमारे पड़ोस में परमाणु और मिसाइल प्रसार में लिप्त रहा है। यह विदित है कि उसने पाकिस्तान को न केवल डिजाइन और विशेषज्ञता प्रदान की है बल्कि वास्तविक परमाणु हथियार और पूरी बैलेस्टिक मिसाइल और क्रुज मिसाइल भी दिया है। इन कृत्यों से चीन ने इस उपमहाद्वीप में स्वाभाविक शक्ति संतुलन को तोड़-मरोड़ दिया है और भारत को बैक फुट पर ला दिया है।

चीन की रणनीतिक चिंतन

आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपका ध्यान चीनी चिंतन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा ; जिसका स्वयं में उतना ही महत्व है जितना अंतर्दृष्टि के लिए जो बीजिंग की रणनीतिक चिंतन को दिया जाता है।

सबसे पहले, वे जिसे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर या सीएनपी कहते हैं, वह भविष्य के सुरक्षा वातावरण के रणनीतिक मूल्यांकन और प्रमुख राष्ट्रों के बीच संबंधों की भविष्यवाणी के लिए एक अनूठा माध्यम बनाता है। सुन जु ने चेतावनी दी थी कि युद्ध का परिणाम दुश्मन की ताकत और कमजोरियों की गणना और अनुमान के माध्यम से शक्ति के सही मूल्यांकन पर निर्भर करता है। इसलिए , सभी संभावना में चीनी रणनीतिकारों द्वारा भारत का आकलन सीएनपी मानदंड के प्रतिकूल नियमित आधार पर किया जाता है।

वर्तमान और भविष्य की ताकत के इस मूल्यांकन में भूभाग , प्राकृतिक संसाधन, सैन्य बल, आर्थिक शक्ति, सामाजिक परिस्थितियां, घरेलू सरकार, विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव जैसे कारकों के समावेश की आवश्यकता होती है। चीनी विश्लेषकों ने सीएनपी का आकलन करने के लिए अपने स्वयं के व्यापक सूचकांक प्रणाली और समीकरण विकसित किए हैं। यह स्पष्ट है कि उनके विश्लेषणात्मक तरीके न तो पारंपरिक मार्क्सवादी -लेनिनवादी हठधर्मिता हैं, न ही पश्चिमी सामाजिक विज्ञान बल्कि कुछ ऐसा जो चीन के लिए अनूठा है।

जहां तक दिलचस्पी का संबंध है, 100 के पैमाने पर अमेरिका 90 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, चीन 60 अंकों के साथ ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी के बाद छठे स्थान पर है और भारत 50 अंकों के साथ दसवें स्थान पर है।

चीनी मस्तिष्क में एक दूसरी बात किसिंजर की पुस्तक से प्रभावित है जिसमें उन्होंने शतरंज और वी कुई की पारंपरिक चीनी खेल के बीच विरोधाभास को दर्शाया है। जहां शतरंज , 32 मोहरों के साथ खेला जाता है जिसमें चेकमेट द्वारा दांव चला जाता है, सीधा हमला और चेकमेट द्वारा जीत हासिल किया जाता है, वहीं वी क्वि को 180 मोहरों के साथ खेला जाता है और जिसमें खाली स्थानों पर कब्जा और विरोधी सामरिक घेरे के माध्यम से अपेक्षित लाभ लेते हुए लंबा अभियान चलाया जाता है। संक्षेप में, जहां अधिकांश देश सीधे संघर्ष के जरिये युद्ध करते हैं वहीं चीनी तरीका प्रतिद्वंद्वी को

कमजोर करना और और मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त करना है। किसिंजर के अनुसार, 1962 का युद्ध हिमालय में वेई कुई खेल का ही एक अभ्यास था।

चीन का अतीत

चीन के उत्थान को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणों और औचित्य की एक समझ इस घटना के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए आवश्यक है। चीन के अतीत की एक संक्षिप्त झलक में तीन प्रमुख कारक हैं जो हमें इस देश के वर्तमान रूख में एक संभावित अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

पहले बात तो चीन की एक शाही परंपरा है जो कई सदियों से चली आ रही है, जिसमें एक सुपरिभाषित केन्द्रीय स्थल जहां हुण जाति के लोगों की संख्या अधिक है, आसपास के राष्ट्रों पर सैन्य प्रभुत्व का इस्तेमाल किया। इस प्रकार चीन के पास ऐतिहासिक रूप से "महान-शक्ति" वाली आत्म-छवि थी, जो संसाधनों की प्रचुरता , आर्थिक आत्मनिर्भरता और शाही राज्य और उसकी आबादी की विशालता को पुष्ट करता था।

दूसरी बात यह है कि एक "महान शक्ति" की छवि गढ़ने के साथ चीनी लोगों में भी विदेशी शक्तियों द्वारा चीन की हार, पराधीनता और अपमान के परिणामस्वरूप एक गहरी बैठा "पीड़ित मानसिकता" का क्षोभ है।

19 वीं शताब्दी के दौरान, चीन ने पश्चिमी सैन्य दबावों का विरोध करने में असमर्थता के कारण अफीम युद्धों और हस्ताक्षर किए , जिसे उन्होंने "असमान संधियाँ" कहा जो संयुक्त राज्य अमेरिका , रूस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ थीं। इन संधियों ने चीन की धरती पर विदेशियों को व्यापार , न्यायिक और अन्य अतिरिक्त -क्षेत्रीय अधिकार प्रदान करके चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया। 1900 में बॉक्सर विद्रोह को रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियों के गठबंधन द्वारा चीन को आक्रमण का अपमान झेलना पड़ा। 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया, और उसके बाद हुए 8 साल के युद्ध में, चीन को निर्दयी इम्पीरियल जापानी सैनिकों के हाथों कम से कम 20 मिलियन लोगों की मौत और कई अत्याचारों का सामना करना पड़ा।

तीसरा; इस "पीड़ित सिंड्रोम" ने विदेशी खतरों पर जोर देने के लिए एक मजबूत आग्रह को तेज करने और एक शक्तिशाली चीनी राष्ट्र के निर्माण को सही ठहराने का काम किया है , जो न केवल अंतरराष्ट्रीय मर्यादा का संकेत है , बल्कि पूर्व में किए गए गलत कार्यों का निवारण भी कर सकता है।

आखिरकार; आंतरिक व्यवस्था और घरेलू कल्याण को बनाए रखने को चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार माना जाता है। आंतरिक अशांति के संबंध में चीन के इतिहास को देखते हुए , कम्युनिस्ट शासन को इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- अध्यक्ष माओ का मानना था कि साम्यवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश को निरंतर क्रांति की अवस्था में रखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने दो आंदोलनों का आयोजन किया : 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड और 1966 में सांस्कृतिक क्रांति, प्रत्येक क्रांति एक दशक तक चली। इन दोनों क्रांतियों ने बहुत कठिनाई उत्पन्न कीं और इसके परिणामस्वरूप कारावास और भुखमरी से लाखों लोग मारे गए। चीनी समाज में गहरे विभाजन और असंतोष की भावना आज तक कायम है।

- वर्तमान कम्युनिस्ट प्रणाली, अभी भी दमनकारी और भ्रष्ट है, जो बाजार की अर्थव्यवस्था के साथ मौजूद है ; और चीनी लोग अक्सर दोनों की संगतता पर सवाल उठाते हैं। अर्थव्यवस्था के साथ -साथ राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य में बदलाव की मांग बढ़ रही है।
- बढ़ती जनसंख्या के साथ सामना करने के लिए , और औद्योगिक तटीय प्रांतों एवं कृषि पर्वतीय इलाकों के बीच तेजी से उभरती हुई आर्थिक असमानताओं के कारण वर्तमान विकास पर आर्थिक विकास के उच्च स्तर को बनाए रखने का भारी दबाव है।
- अंत में; पिछली शताब्दी में चीन में शामिल तिब्बत , सिंकियांग, मंगोलिया और मंचूरिया जैसे गैर -हान बहुमत वाले क्षेत्रों में जातीय तनाव में बढ़ोतरी हो रही है। जातीय हिंसा का अक्सर फैलना राष्ट्र की असुरक्षा के एक अतिरिक्त स्रोत का प्रस्तुत करता है।

इस पृष्ठभूमि में हम अंत में पीएलए की नौसेना की ऐतिहासिक विरासत को देखें।

पीएलए की नौसेना की विरासत

चीन दावा करता है कि उसकी समुद्री परंपरा बहुत प्राचीन है और इसकी जड़ें पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हैं , जिसने महत्वपूर्ण नौवहन और जहाज निर्माण नवाचारों को जन्म दिया, तथा एशिया और अफ्रीका के लिए कई व्यापारिक मार्गों को खोला। मिंग राजवंश (1368-1644) की प्रारंभिक 15 वीं शताब्दी की कथाएँ, एडमिरल चेंग हो के विशाल बेड़े के उल्लेखनीय बेड़े का वर्णन करती हैं , जो सेना, खजाने, माल और खाद्य पदार्थों को ढ़ोया करते थे ; जिसने भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका में सात विशाल यात्राएँ कीं। प्रभावशाली चीनी नौसैनिक शक्ति का यह युग मात्र 30 वर्षों तक चला, क्योंकि राजकोषीय और राजनीतिक मजबूरियों के कारण मिंग सम्राट को आगे की यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और चेंग के "खजाने के बेड़े" को नष्ट करने का आदेश दिया।"

अगली कुछ शताब्दियों में , उत्तर और पश्चिम के खतरों को दूर किया , और यह सुनिश्चित किया कि चीन की नौसैनिक शक्ति क्षीण बनी रहे और इसलिए , 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में समुद्र के रास्ते आए यूरोपीय साम्राज्यवादियों को खदेड़ने में असमर्थ थी। पश्चिमी वाणिज्यिक और सैन्य दबावों का विरोध करने की चीन की असमर्थता के कारण अफीम युद्ध हुए और "असमान संधियों" पर हस्ताक्षर किए गए जिसका जो मैंने उल्लेख किया था।

मई 1950 में अपनी आधिकारिक स्थापना पर पीएलए नौसेना (पीएलएएन) सोवियत संघ द्वारा दिए गए युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लैस था, जिन्होंने प्रशिक्षण और रखरखाव संबंधी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में भी मदद की। 1960 में एक दशक की लंबी सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन -सोवियत गठजोड़ में दरार आना पीएलएएन के लिए बड़ा झटका था और जिससे इसके तकनीकी विकास में बाधा उत्पन्न हुई।

यह उल्लेखनीय है कि 1960 के चीन-सोवियत सैद्धांतिक विच्छेद से बहुत पहले चीनी नेतृत्व ने बड़े पैमाने पर सोवियत हथियार प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित चोरी का आदेश दिया था। एक बार जब वास्तव में विच्छेद हो गया तो 1960 के मध्य में चीनी नेतृत्व ने सोवियत प्रौद्योगिकी के पुन: निर्माण के आधार पर आत्मनिर्भरता की सामान्य नीति की घोषणा की। यह एक रिवर्स इंजीनियरिंग परियोजना थी, जिसे मंदारिन में गॉचन्हुआ कहा जाता है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया।

चीन का समुद्री दृष्टिकोण

चीन के शुरुआती समुद्री दृष्टिकोण को सोवियत नौसेना सिद्धांत के साथ -साथ कम्युनिस्ट हठधर्मिता को प्रसारित करने के लिए 2000 या इससे अधिक स्टाफ कमांड और यूनिट स्तर पर सोवियत संघ द्वारा तैनात नौसेना सलाहकारों द्वारा आकार दिया गया था। इस सिद्धांत ने समुद्र में "गुरिल्ला युद्ध" करने के लिए छोटी नौकाओं और पनडुब्बियों का उपयोग करते हुए पूंजीवादी नौसेनाओं द्वारा उभयचर हमले के खिलाफ तटीय रक्षा पर जोर दिया। यहां तक कि जब सोवियत नौसेना ने क्यूबा मिसाइल संकट के बाद एक नाटकीय परिवर्तन किया , तो पीएलएएन सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से अपने तटीय रक्षा और लोगों के युद्ध के सिद्धांतों से जुड़ा रहा।

यह 1982 में डेंग शियाओपिंग के आर्थिक सुधारों, परमाणु पनडुब्बियों को शामिल करने और पीएलए नौसेना के कमांडर के रूप में जनरल लियू हुआंग की नियुक्ति का एक संयोजन था जिसने अपेक्षित रूप से अगोचर तटीय बल से लेकर बीच समुद्र में नौसेना को बनाए रखने के लिए अपनी परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। वोरोशिलोव नौसेना अकादमी से स्नातक पास लियू के पास एक मजबूत तकनीकी पृष्ठभूमि थी और पीएलएएन के लिए एक रणनीति की रूपरेखा तैयार की जो इसे 21 वीं शताब्दी के मध्य तक विमान वाहक और वैश्विक पहुंच सहित चौतरफा युद्धक क्षमता प्रदान करती। स्वदेशी निर्माण, रिवर्स इंजीनियरिंग और आयात के संयोजन के माध्यम से जो प्रभावशाली बल उभरते हुए हम देखते हैं, वह काफी हद तक लियू के दृष्टिकोण का परिणाम है।

सेना के एक पूर्व अधिकारी, लियू केंद्रीय सैन्य आयोग में बहुत प्रभावशाली थे और एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। इस प्रकार, उनके पास अपने दृष्टिकोण को आगे ले जाने का प्रभाव था जिससे पीएलएएन "तटीय रक्षा" प्रतिमान से "अपतटीय रक्षा" में चला गया और फिर तीन चरणों में चीन के प्रभाव में लाने के लिए "अपतटीय" शब्द को विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में विभाजित किया गया।

चरण 1 में जिसे 2000 तक प्राप्त किया जाना था; पीएलएएन को "प्रथम द्वीप श्रृंखला" द्वारा परिसीमित क्षेत्र में स्थापित करना था , जिसे कुरील द्वीप समूह , जापान, ताइवान, फिलीपींस, बोर्नियो और इंडोनेशिया के उत्तरी सिरे के माध्यम से चल रही एक रेखा द्वारा परिभाषित किया गया है। लियू की रणनीति के चरण 2 में "द्वितीय द्वीप श्रृंखला" के नियंत्रण की परिकल्पना की गई थी , जो कि वर्ष 2020 तक मध्य प्रशांत में जापान , मारियानस और कैरोलिन द्वीप के दक्षिण में 2000 मील की दूरी पर गुजरने वाली एक रेखा द्वारा चिह्नित है। तीसरे और अंतिम चरण में पीएलएएन को 2050 तक एक वैश्विक बल बनाने की परिकल्पना की थी।

चरण 1 की प्राप्ति न होने का पीएलएएन रणनीतिकारों की चेतना पर भारी बोझ पड़ा , क्योंकि पहली द्वीप श्रृंखला को भौगोलिक बाधा के रूप में देखा गया है जो चीन को बीच समुद्र तक पहुंच में बाधा डालती है। चीनी धारणा में यह एक "नाकाबंदी" है जो पीएलएएन बलों के पाबंदी को सक्षम बना सकता है। इस संदर्भ में, ताइवान को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में माना जाता है, जिसे अगर पीआरसी में बहाल किया गया, तो बाधा अवरोधक टूट जाएगा और प्रशांत क्षेत्र में आक्रमण और रक्षा के लिए एक प्रमुख समुद्री आधार के निर्माण को सक्षम बनाएगा।

ताइवान में स्थित पीएलएएन बल द्वितीय द्वीप श्रृंखला के जल निकायों को भी नियंत्रित कर सकता है और गुआम में स्थित अमेरिकी संपत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। जब तक यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता है , यह माना जाता है कि पीएलएएन किसी भी विरोधी नौसेना को मातृभूमि के चारों ओर के पानी में पहुंच बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए समुद्र में न जाने देने की रणनीति का पालन करेगा।

कुछ साल पहले तक समुद्री संदर्भ में पीएलए प्रतिष्ठान में असुरक्षा की एक अंतर्निहित भावना को महसूस किया जा सकता था। पीएलए नौसेना द्वारा अपने जल क्षेत्रों से बाहर निकलने या बहु -राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने एवं 2004 की सुनामी राहत जैसी मानवीय सहायता के प्रति उनकी अनिच्छा में यह अंतर स्पष्ट था। हालाँकि, यह सब दिसंबर 2008 में सोमालियाई जल क्षेत्र में एक विस्तारित एंटी-पायरेसी गश्ती के लिए एक कृतक बल को भेजने के साथ बदल गया प्रतीत होता है। तब से अफ्रीका के हॉर्न से दूर एक केन्द्र पर लगातार पीएलए नौसेना के कृतक बल मौजूद हैं। जहां इन तैनाती का प्राथमिक उद्देश्य अदन की खाड़ी में गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को समुद्री लुटेरों की पाइरेसी से बचाव करना है, वहीं उनकी सफलता ने चीन के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और अपने विदेशी हितों की रक्षा के लिए समुद्री शक्ति का उपयोग करने का संकल्प लिया है।

पीएलए नौसेना की रूपरेखा

पीएलएएन की 21 वीं सदी की समुद्री रणनीति निम्नलिखित व्यापक मिशन को शुरू करने के लिए परमाणु पनडुब्बियों और नौसेना विमानन द्वारा समर्थित भूतल-जहाजों का आह्वान किया:

- हिंद और प्रशांत महासागरों में मिलने वाले महत्वपूर्ण एसएलओसी की रक्षा।
- ताईवान का स्वतंत्रता की ओर किसी भी प्रयास को रोकना।
- दक्षिण और पूर्वी चीन सागरों के जल क्षेत्रों में चीनी भूभाग के दावों का प्रवर्तन।
- अमेरिका, रूस और भारत के विरूद्ध विश्वसनीय जलतल परमाणु निवारक को बनाए रखना।

पीएलए नौसेना के समुद्री बलों को नामोद्दिष्ट उत्तरी समुद्री बेड़े , जिसका मुख्यालय क्विंगडाओ , डिंगहाई मुख्यालय के साथ पूर्वी समुद्री बेड़े और झेन जियांग मुख्यालय के साथ दक्षिण समुद्री बेड़े के तीन भौगोलिक कमान आबंटित किए गए है। एक नौसैनिक वायु सेना , जिसमें 25 एयर-बेस से आक्रमण , वायु रक्षा, एएसडब्ल्यू और एमआर विमान परिचालन शामिल है, तीन बेड़े के बीच विभाजित है।

अपनी निर्धारित भूमिकाओं और मिशनों का निर्वहन करने के लिए , पीएलए नौसेना ने एक महत्वाकांक्षी अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है जो स्वदेशी उत्पादन और आयातित प्लेटफार्मों का मिश्रण है। प्रमुख लड़ाकू विमानों के मामले में वर्तमान पीएलए नौसेना की ताकत है; 28 विध्वंसक, 52 फ्रिगेट, 65 पनडुब्बी और 290 विमान।

कतिपय नए महत्वपूर्ण जहाज, पनडुब्बियां और विमान निम्न प्रकार है:

- रूसी *सोवरेमेमिय* क्लास 8000 टन गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रायर जो *मोस्किट* एसएसएम और दो *कामोव* हेलिकॉप्टर से युक्त है।
- 7000 टन का *ल्युजोउ* क्लास एयर डिफेंस डेस्ट्रॉयर जो 150 किमी रेंज वाले *लुयांग* और जियांकायी क्लास के मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की उन्नत रूसी एस-300 एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली से युक्त है। ये सभी चीन निर्मित हैं और सबमें स्टील्थ फीचर हैं।
- डिजल पावरयुक्त रूस निर्मित किलो क्लास पनडुब्बी जिसमें जहाज रोधी और भूमि आक्रमण क्लब मिसाइल लगा हो।
- चीन निर्मित *सोंग* और *युआन* श्रेणी का डीजल चलित नौका।

वर्तमान में , ताइवान के संदर्भ में यदि मजबूत अमेरिकी सेनाओं का सामना हो , तो पीएलए नौसेना को एएसडब्ल्यू और वायु-युद्धरोधी क्षमताओं की कमी सहित कई गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इन कमियों को दूर करने के लिए पीएलए नेवी इस क्षमता को विकसित करने में लगा हुआ है जिसे अमेरिकी "एंटी-एक्सेस" और "एरिया इनकार" या "ए2एडी रणनीति" कहते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य है अनिवार्य रूप से ताइवान जलडमरूमध्य सहित दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक युद्ध समूहों की पहुंच को रोकना है।

ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित ए 2एडी रणनीति को दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं द्वारा रेखांकित किया गया है। एक अवधारणा है कि डॉंग फेंग -21डी बैलिस्टिक मिसाइल के एक संस्करण का विकास है जो सैद्धांतिक रूप से चीन के तट से 900 मील दूर एक तेज गति वाले वाहक समूह को संलग्न कर सकता है। दूसरी अवधारणा यह है कि क्रूज -मिसाइलों, पनडुब्बियों, तट-आधारित विमान और माइनफील्ड्स से जुड़े स्तरित रक्षा माध्यम से नुकसान पहुंचाया जाए। यह भी बताया गया है कि द्वितीय आर्टिलरी कोर अब तक चीन के परमाणु निवारक भंडार को पारंपरिक रूप से सशस्त्र मिसाइलों के साथ जहाज और किनारे के लक्ष्यों के खिलाफ एक द्वितीय आक्रमण का भार सौंपी गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी नौसेना के आधुनिकीकरण की योजना ताइवान की मुख्य भूमि के शासन बहाली से परे है और यह कि पीआरसी लंबे समय तक हिंद-प्रशांत जल क्षेत्र पर पीएलएएन के लिए अधिक विस्तृत भूमिका की सुविधा के लिए शक्ति -प्रक्षेपण क्षमता बनाने में लगी हुई है। इसलिए , ए2एडी रणनीति एक अंतिम उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो अनुमान लगाने के लिए खुला है।

विमान वाहक की खोज

मुख्य रूप से चीन इस भाव से विमान-वाहक को प्राप्त करने का आग्रह करता है कि उच्च समुद्र पर तैनात उनकी नौसेना बल अभिन्न वायु शक्ति के बिना अप्रभावी है। यह इस नौसेना के इरादे का स्पष्ट संकेत है कि विस्तारित समयावधि में दूर के जलक्षेत्र में काम करने के लिए है। उनकी एंटी-पाइरेसी तैनाती ने यह दर्शाया है कि विदेशी जल क्षेत्र में या प्रतिकूल तटों के करीब हमेशा चौबीस घंटे हवा की सहायता के अभाव में ऐसी शक्तियों के बहुआयामी खतरों से घिरने की आशंका रहती है। एक वाहक को एक प्रमुख प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है ; जैसा कि जनरल लियांग गुआंगली के 2009 के बयान से स्पष्ट है कि चीन एकमात्र बड़ा राष्ट्र था जिसके पास विमान वाहक नहीं थे और यह घोषणा की कि ऐसी स्थिति हमेशा नहीं बनी रह सकती है।

1985 की शुरूआत से चीनी सेना ने सेवानिवृत्त तीन हल्क विमान वाहक का अधिग्रहण किया - एक ऑस्ट्रेलिया से और दो यूक्रेन से, जो इस तरह के जहाज के रिवर्स इंजीनियरिंग का अध्ययन करने और एक मास्टर-प्लान के हिस्से के रूप में था। वर्ष 2000 में 20 वर्ष पुराना 65,000 टन *वेरीयाग* यूक्रेन से खरीदा गया था और डालियान में एक शिपयार्ड के पास रखा गया था। लगभग एक दशक तक *वेरीयाग* की किस्मत अटकल का विषय बना रहा , लेकिन अब यह पता चला है कि जहाज को व्यापक समुद्री परीक्षणों के बाद 25 सितंबर को पीएलएएन में *लियाओनिंग* के रूप में नियुक्त किया गया था।

जहां तक *लियाओनिंग* के लिए विमान की उपलब्धता का सवाल है , ऐसी अटकलें हैं कि यह जे -15 फ्लाइंग शार्क; सुखोई-33 वाहक-वहन सेनानी का एक रिवर्स -इंजीनियर संस्करण होगा। तथापि, मुख्य संदेह बना रहा ; इस नई विकसित मशीन की स्थिति और निकट भविष्य में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए जहाज की तत्परता दोनों के बारे में। दूसरे शब्दों में, इस जहाज को परिचालन मंच घोषित किए जाने से पहले पीएलएन को कई क्षेत्रों में काफी दूरी तय करनी होगी।

तथापि, *लिओनिंग* निश्चित रूप से चीन द्वारा हिंद -प्रशांत जल क्षेत्र में वाहक -जनित वायु-शक्ति को तैनात करने के इरादे की घोषणा है और यह हमारे लिए एशिया -प्रशांत व हिंद महासागर में अपने तत्काल समुद्री पड़ोसियों के साथ-साथ विचार के लिए एक विषय होना चाहिए।

परमाणु पनडुब्बी शक्ति

पीएलए नेवी ने 1974 में अपनी पहली *हान* श्रेणी की परमाणु चालित पनडुब्बी को समुद्र में भेज दिया था लेकिन जाहिर है कि रिएक्टर और अन्य समस्याओं ने इस श्रेणी की नौकाओं को परिचालनात्मक प्रभाव प्राप्त करने से रोका है और अक्सर बहुत दूर तक जाने का जोखिम उठाया है। *हान* के बाद और अधिक सफल *शांग* एसएसएन आया और उनके बैलिस्टिक-मिसाइल उप -क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा ये इकाइयां एक प्रमुख चीनी समुद्री निषेध क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो वर्तमान में प्रशांत और निकट भविष्य में हिंद महासागर में होगी।

चीन की एकल *ज़िया* श्रेणी की परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को नई *जिन,* जिसे पहली बार 2010 में, हैनान में पनडुब्बी बेस के पास देखा गया था, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। बारह 8000 किमी रेंज की जू लॉन्ग -2 एसएलबीएम मिसाइलों की बैटरी से लैस यह पनडुब्बी दक्षिण चीन सागर से सैन फ्रांसिस्को और नई दिल्ली दोनों को निशाना बना सकती है , 5-6 नौकाओं की यह नई श्रेणी चीनी परमाणु निवारक के लिए एक बड़ी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करेगी।

यद्यपि चीनी परमाणु पनडुब्बी तकनीकी रूप से निम्न हो सकती हैं और अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में शायद कमतर हैं किंतु वे यूएसएन वाहक युद्ध समूह के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जहां तक भारत और क्षेत्र का संबंध है नई जिन श्रेणी एसएसबीएन चीन को अधिक शक्तिशाली शक्ति के साथ संपन्न करता है और शायद अमेरिका के पहले हमले के खिलाफ एक बेहतर निवारक।

भारत का समुद्री दांव

तब तार्किक प्रश्न यह होगा कि वास्तव में भारत के लिए लड़ाई के उभरते हुए पीएलएएन व्यवस्था के निहितार्थ क्या हैं ? संक्षेप में, वैश्विक महत्व के देश के रूप में भारत का उदय उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है , जो बदले में वैश्विक व्यापार से जुड़ा हुआ है। विश्व अर्थव्यवस्था की हालिया मंदी के बावजूद , भारत का व्यापार और वाणिज्य प्रभावी बना हुआ है। 2006 और 2012 के बीच भारत का विदेशी व्यापार तीन गुना बढ़कर 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसका बड़ा महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा जो 2006 में मामूली रूप से 0.9% था, 2012 में नाटकीय रूप से दोगुना होकर 1.8% हो गया है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

चूंकि इस व्यापार और ऊर्जा यातायात का 95% से अधिक समुद्र द्वारा किया जाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से पुनरुत्थानशील भारत की समृद्धि इसके समुद्री लेन पर निर्भर है।

हिंद महासागर में सालाना 100,000 से अधिक व्यापारी जहाजों की आवाजाही होती है , जो एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के व्यापार और ऊर्जा का परिवहन करते हैं। पायरेसी होती है ; ऊर्जा या वस्तुओं की आपूर्ति में कोई गंभीर व्यवधान, कीमतें आसमान छू सकती हैं , और दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर सकती हैं। उस भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए कि एक शत्रु नौसेना के युद्धपोत , पनडुब्बी और विमान इस यातायात को बाधित कर सकते हैं।

समुद्री प्रतिक्रिया

जैसा कि हमने पहले चर्चा की , वृहद स्तर पर, अगले कुछ दशकों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था की गिरावट देखी जा रही है, और इसके साथ उसकी समुद्री शक्ति और वैश्विक प्रभाव में भी कमी आएगी। यह आर्थिक , औद्योगिक और सैन्य क्षेत्रों में चीन के अभूतपूर्व उत्थान के साथ होगा और यह अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के संदर्भ में सहवर्ती लाभ के साथ होगा। क्षेत्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक इच्छुक और उपयोगी हथियार के रूप में उपयोग कर चीन द्वारा भारत के प्रति अपनी सख्त रूख बनाए रखने की संभावना है।

हाल के दिनों में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश , पाक अधिकृत कश्मीर पर मुद्रा परिवर्तन और दक्षिण चीन सागर पर नए सिरे से दावे में चीन की तल्ख मुद्रा को देखते हुए ऐसी आशा है कि हमारे राजनयिक सही तरीके से संकेतों को पढ़ रहे हैं।

हिमालय की सीमाओं के साथ चीन -भारतीय सैन्य समीकरण, वायु सेना के ठिकानों , मिसाइल स्थल और सैन्य संरचनाओं के सापेक्ष भौगोलिक स्थान को देखते हुए संचार की लाइनों की गुणवत्ता चीन का पक्ष मजबूत है। इसके अलावा, चीन-भारत संघर्ष के मामले में पाकिस्तान एक दूसरा मोर्चा खोलकर तत्काल समर्थन प्रदान करेगा। इन परिस्थितियों में , भारतीय सेना और वायु सेना को जो सबसे अच्छा मिल सकता है , वह एक अनिश्चित गतिरोध है। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि हमें समुद्र की ओर देखने और यह जांचने की आवश्यकता है कि समुद्री क्षेत्र में हमें क्या मिल सकता है?

अमेरिकी विश्लेषक रॉबर्ट कैपलान के अनुसार चीन को चिंता है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को "मलक्का *जलडमरू के पश्चिमी प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए धातु की शृंखला*" के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रकार व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा। राष्ट्रपति हू जिंताओ ने खुद भी चीन की "मलक्का दुविधा" के संदर्भ में इसी तरह की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया है।

भारतीय नौसेना के विकास को पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि अगले कुछ दशकों में इसकी सेवा हिंद महासागर में अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके और सभी चुनौतियों का सामना कर सके।

हमारे नौसैनिकों पर हावी होने की क्षमता और जरूरत पड़ने पर हिंद महासागर की समुद्री गलियों को बड़े सुरक्षा कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए। यह भारत के हित में है कि हिंद महासागर को अखाड़ा बनाया जाए , जिसमें हमारी समुद्री सेनाओं को एक प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए लाया जा सके।

इसलिए जहां भारत को अपने अमूल्य समुद्री लाभ का फायदा उठाने का उपकरण तैयार करना है वहीं यह आवश्यक है कि हम अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने और अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट दीर्घकालिक रणनीतियों का एक सेट तैयार करें।

रणनीतियां

चीन का अनवरत उदय भारत के लिए एक अस्तित्वगत दुविधा उत्पन्न करता है और खतरों या जबरदस्ती का मुकाबला करने के लिए हमारे सामने विकल्प कठोर है। या तो हम अपनी आर्थिक वृद्धि में तेजी लाएं और अपने दम पर खड़े होने के लिए सैन्य ताकत को बढ़ाएं या हम उन साझेदारों के साथ गठबंधन करें जिनके अभिप्रेत लक्ष्य हैं। यदि दोनों संभव न हो तो हमारे राजनयिकों को एक गंभीर टकराव से बचने और और समय लेने के सभी प्रयास करने चाहिएं। तथापि , अंतरिम रूप से कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिन पर हमें राष्ट्रीय रणनीति के हिस्से के रूप में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

पहले तो हमें युद्धस्तर पर स्वदेशीकरण करने की आवश्यकता है। जहां चीन सालाना 2 बिलियन डॉलर के हथियारों का निर्यात करता है वहीं भारत को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एमएस आयातक होने का सबसे बड़ा गौरव प्राप्त है। 1960 में चीन-सोवियत विभाजन के दो दशकों के भीतर चीन ने अपने सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक प्रमुख हथियारों और भारी मशीनरी के रिवर्स इंजीनियरिंग को पूरा किया था और सतत उत्पादन के तहत सोवियत मूल की प्रणालियों में बैलिस्टिक मिसाइल, डीजल और परमाणु पनडुब्बियां, लड़ाकू विमानों और विध्वंसक, फ्रिगेट और गश्ती शिल्प की मिग - 21 श्रृंखला शामिल हैं।

दूसरी बात यह है; भारत का जहाज निर्माण उद्योग एक रणनीतिक संपत्ति है जिसे नौसेना द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित और निर्देशित किया जाना चाहिए। तत्काल आधुनिकीकरण करने के अलावा शिपयार्ड को निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने, अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

तीसरी बात: शांति काल में देश के लिए नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कूटनीति के साधन के रूप में है , जो राजनीतिक उद्देश्यों और विदेश नीति की पहल के लिए सहायता प्रदान करता है।

विदेश मंत्रालय के समन्वय से हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र में हमारे समुद्री पड़ोसियों तक पहुंचने और प्रशिक्षण, हार्डवेयर और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

आखिरकार; हमारी समुद्री सेनाएं वर्तमान में दुर्जेय रेंज और क्षमता से युक्त हथियारों , सेंसर और प्लेटफार्म शामिल हैं। विमानवाहक पोत विक्रमादित्य को शामिल करने के साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल और पनडुब्बियों की नई श्रेणियों जैसी प्रणालियों से समुद्र में हमारी क्षमताएं और बढ़ जाएगी। उनकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए हमें नेट-वर्क ऑपरेशन की एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें नौसैनिक इकाइयां एक समर्पित समुद्री संचार उपग्रह के माध्यम से पूरे हिंद महासागर को कवर करने वाले कमांड और कंट्रोल नेटवर्क का हिस्सा बन सके।

निष्कर्ष

पीएलएएन के पास तेजी से विकसित हो रहा पृष्ठ जहाजी बेड़ा है और देश में ही निर्मित परमाणु पनडुब्बियों की ताकत अब परिचालन तैनाती के लिए तैयार है। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में है और अधिक संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण चल रहा है। यह नौसेना विश्व स्तरीय बल बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए अपनी संगठनात्मक संरचना, सिद्धांत और प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन में भी सुधार कर रही है। अफ्रीका के

हॉर्न में विस्तारित पीएलए नौसेना एंटी -पायरेसी गश्ती दल ने दूर स्थित जलक्षेत्र में तैनाती के लिए अपने कौशल को बढ़ाने में मदद की है।

जैसा कि चीन उत्तरोत्तर अपनी समुद्री पहुंच और क्षमता को नियंत्रित करने के लिए विस्तार कर रहा है, पहले अपने नजदीकी समुद्रों और फिर बड़े प्रशांत क्षेत्र में तो इससे एशिया-प्रशांत में मौजूदा व्यवस्था के लिए चुनौती अवश्य ही खड़ी होगी। अमेरिका इस शक्ति-संक्रमण का प्रबंधन किस प्रकार करेगा यह भारत के लिए बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि यह तय करेगा कि पीएलएएन हिंद महासागर के जल क्षेत्रों में कैसे और कब आगे बढ़ता है। जब ऐसा होगा, तो चीन कितनी दूर तक आधिपत्य बढ़ा पाएगा? और इस प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए किस स्तर का जोर होगा? अंतरिक्ष और साइबर युद्ध में अपने प्रदर्शन के अलावा, चीन ने नई समुद्री अवधारणाओं को विकसित किया है जो अमेरिकी नौसेना गंभीर रूप से चिंतित हैं। इसी तरह की चिंता भारतीय नौसेना पर जल्द ही होने वाली है। बेहतर होगा कि हम पूरी गंभीरता के साथ उनके बारे में सोचना शुरू करें।

उनके लंबे समय से क्षेत्रीय विवादों , संबंधित भू -रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह मानना बचकाना होगा कि चीन और भारत के रूप में इस तरह के निकटता में वे शांतिपूर्ण तरीके से विकास करें। अंत में, हमें लगातार यह याद रहना चाहिए कि चीनी नेता एक रणनीतिक संस्कृति तैयार करते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में युद्धाभ्यास के लिए सूक्ष्मता पर निर्भर करती है। वे आशा करते हैं कि इस तरह से विरोधियों की इच्छा को झुकाएंगे और युद्ध में उलझे बिना जीत हासिल करेंगे।

****